Reliance
Industries Limited

March 20, 2014

BSE Limited
Phiroze Jeejeebhoy Towers
Dalal Street
Mumbai 400 001

National Stock Exchange of India Limited
Exchange Plaza
Plot No.C/1, G Block
Bandra-Kurla Complex
Bandra (East)
Mumbai 400 051

Scrip Code: 500325
Fax No.2272 2037 / 2272 3719

Trading Symbol: "RELIANCE EQ"
Fax No. 2659 8348 / 2659 8237 /38

Dear Sirs,

Sub: Allegations of benefits from Gujarat Government – Hindi transcript of Video Recording

We enclose a copy of Hindi transcript of the Video Recording uploaded by the Company on You Tube (link http://bit.ly/1lSw8zg) in connection with the Allegations of benefits from Gujarat Government, for your perusal and information.

Thanking you,

Yours faithfully,
For **Reliance Industries Limited**

S. Sudhakar
Vice President
Corporate Secretarial

Encl.: As above

Copy to:
The Luxembourg Stock Exchange
Societe de la Bourse de Luxembourg
SA11, Avenue de la Porte-Neuve
B P 165, L – 2011
Luxembourg

Reliance
Industries Limited

Allegations of benefits from Gujarat Government – Hindi transcript of Video Recording

आज बात करते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड और गुजरात के एक मंत्री के आपसी रिश्तों की। आरोप ये लगाया जा रहा है कि इन मंत्री के कारण रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को बहुत फायदा हुआ है। जरा देखते हैं कि इस आरोप में कोई दम है या नही। ये बात सही है कि इन मंत्री के साथ जिनके पास गैस, पैट्रोलियम, उत्खनन यानि खनन और उर्जा का विभाग है और ये भी सही है कि इनके अम्बानी परिवार के साथ रिश्ते हैं। पर ज़रा देखें, एक एक क्षेत्र को लेकर कि क्या इन्होंने कोई फायदा पहुंचाया है या फायदा पहुंचाने की स्थिति में भी हैं।

पहला विषय है उनके पास गैस का, जोर शोर से कहा जा रहा कि गैस के क्षेत्र में चूंकि मंत्री के साथ रिश्ते है इसलिए फायदा पहुंचाया जा रहा है। हैरानी की बात है जहॉ रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड गैस निकाल रही है वो आंध्र प्रदेश के तट के पास है, जो कि गुजरात से कम से कम 1500 किलोमीटर दूर है। दूसरी बात गैस केंद्र सरकार का विषय है राज्य सरकार का विषय नहीं है।

एक और बात उनके पास विभाग है पैट्रोलियम का, अब पैट्रोलियम में वो कैसे फायदा पहुंचा सकते हैं। यह भी संविधान के अनुसार केंद्र सरकार का विषय है और जो रिफ़ायनरी गुजरात में लगी है वो डी-रेगुलेटिड है वहॉ कोई भी व्यापार कर सकता है और बहुत पुरानी लगी हुई है, उसमें वो मंत्री कैसे फ़ायदा पहुंचा सकते हैं।

तीसरा है खनन का विषय, खनन में राज्य सरकार के हाथ और केंद्र सरकार के हाथ कुछ कुछ शक्तियॉ होती हैं, लेकिन हम बिलकुल स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि गुजरात में माइनिंग में रिलायंस इंडस्ट्रीज़ कोई काम नहीं कर रही।

और चौथा विषय आता है उर्जा का, उर्जा यानि पॉवर, हम बताना चाहते हैं कि गुजरात में जो हमारे उद्योग और कारोबार हैं उनमें हमें बिजली कैप्टिव पॉवर प्लान्ट से मिलती है। इसका मतलब हुआ हमारे खुद के अपने बिजली घर हैं, बिजली बनाते है अपने उद्योगों को देते हैं।

इसलिए इन मंत्री से हमको बहुत फ़ायदा पहुंच रहा हैं ये बात एकदम बेबुनियाद, निराधार, राजनीति से प्रेरित और आपको भरमाने के लिये है। हमें देखना चाहिए संविधानिक व्यवस्था क्या है। संविधान के अनुसार जो विषय हैं उनमें उन मंत्री का दख़ल नही है वो चाहें भी तो हमें फ़ायदा नही पहुंचा सकते।